जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 255 प्रभात बीकानेर, शुक्रवार 10 अप्रैल, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस महिला आरक्षण विधेयक पर ''परमैप्शन वार'' नहीं हारना चाहती भाजपा से

इसीलिए शुक्रवार को सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक बुलाई है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। कांग्रेस कार्यसमिति कल दोपहर 3 बजे बैठक करेगी, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी और विधेयक के समर्थन को दर्ज किया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों और सुधारों के साथ।

सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रति गंभीर हैं। वहीं, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और विधेयक को रोकने के लिए रोडब्लॉक्स बना रहा है।

कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया है कि दक्षिण भारत के राज्यों के साथ भेदभाव होगा, क्योंकि सीमांकन 2011 की जनगणना के अनुसार होगा, जिससे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य बहुत लाभ में रहेंगे, जबकि छोटे राज्य और दक्षिण के राज्य नुकसान में।

स्थिति ऐसी हो जाएगी कि केन्द्र में सरकार के गठन में दक्षिण के राज्यों की भूमिका लगभग नगण्य हो जाएगी,

- **बैठक का मुख्य एजेण्डा है, महिला आरक्षण विधेयक, जो संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र में पेश करेगी भाजपा सरकार**
- **कांग्रेस का मानना है, हालांकि भाजपा सरकार जानती है कि पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण, सरकार का यह विधेयक पारित नहीं हो सकेगा, पर भाजपा को प्रचारित करने का मौका मिल जायेगा कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस यह महिला विधेयक पारित कराने के पक्ष में नहीं है और व्यर्थ में बाधाएं उत्पन्न कर रही है।**
- **इस ''परसैप्शन'' (बोध) को प्रचारित होने से रोकने के प्रयास में, कांग्रेस भी विधेयक का समर्थन करेगी।**
- **यह संसद का विशेष सत्र बंगाल व तमिलनाडु के चुनाव से कुछ पहले ही आहूत किया गया है, अतः कांग्रेस के लिये और भी जरुरी हो गया है, चुनाव में पार्टी की कोई गलत छवि न पहुंचे।**
- **कांग्रेस परिसीमन पर भी अपना सोच पहुंचाना चाहती है कि इस नए परिसीमन से दक्षिण भारत को भारी राजनीतिक नुकसान होगा, तथा उत्तर भारत ही निश्चित करेगा, देश का राजनीतिक एजेण्डा।**

क्योंकि उत्तर भारत का प्रभाव यह तय करेगा कि केन्द्र में कौन सरकार बनाएगा।

कांग्रेस द्वारा उठाया गया दूसरा मुद्दा आरक्षण (कोटा) का है। इसके तहत, वे ओबीसी आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, जो पहले कुछ राजनीतिक पार्टियों, जैसे जनता दल, की मांग थी और कांग्रेस ने जिसका विरोध किया था।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस धारणा सम्बन्धी युद्ध में पीछे नहीं रहना चाहते, क्योंकि यह विशेष तीन दिवसीय सत्र पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों के बहुत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पोकरण में 10 चिंकारा हिरणों का शिकार

पोकरण, 9 अप्रेल (निसं)। पोकरण क्षेत्र के लोहारकी, रामदेवरा इलाके में 10 चिंकारा हिरणों के शिकार का मामला सामने आने के बाद वन्यजीव प्रेमियों में भारी रोष देखने को मिला। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने एक साथ 10 चिंकारा हिरणों का शिकार किया है।

घटना के बाद वन विभाग की ओर से समय पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज पर्यावरणप्रेमी और

- **दस दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी।**

वन्यजीवप्रेमी सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने पोकरण वन विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व वन्यजीव प्रेमी धर्मेन्द्र पूनिया ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। साथ ही, अधिकारियों को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई।

युद्ध में अपनी बिचौलिए की भूमिका से अति प्रसन्न है पाकिस्तान

इस्लामाबाद को पूरी तरह सजाया गया है, दो दिन की छुट्टी घोषित की गई है तथा सुरक्षा का पुख्ता इन्तजाम किया गया है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। दशकों बाद पाकिस्तान फिर से महत्वपूर्ण महसूस कर रहा है। इस्लामाबाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति के आगामी दौरे के लिए अपनी सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने के हर उपाय कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिकी-ईरान बैठक से पहले सार्वजनिक छुट्टियों की घोषणा की है।

पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वह आगंतुक गणमान्य व्यक्तियों को सम्पूर्ण सुरक्षा कवच देगा। अचानक वैश्विक मंच पर उभरने के साथ, पाकिस्तान विश्व में अपनी मौजूदगी का जोर शोर से अहसास करवा रहा है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें डॉनल्ड ट्रंप के सहयोगी स्टीव विटकॉफ़ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर शामिल हैं। ईरानी टीम का नेतृत्व उनके राष्ट्रपति

- **पर, पाकिस्तान द्वारा कराई गई ''सीज़फायर'' अभी से लड़खड़ाती हुई सी नज़र आ रही है।**
- **बात तो यह है कि अमेरिका द्वारा बहुप्रचारित घोषणा कि, ''स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़'' से जहाजों का निर्बाध आवागमन चालु हो जायेगा, कागज़ी घोषणा से आगे नहीं बढ़ी है।**
- **साथ ही अभी से मतभेद उत्पन्न हो गये हैं कि लेबनान व हिज्बुल्लाह ऑपरेशन, वर्तमान ''सीज़फायर'' समझौते में शामिल हैं या नहीं। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रुप से कहा कि ये दोनों समझौते का अंग हैं पर, ट्रंप इस बात से साफ इन्कार कर रहे हैं।**
- **दोनों पक्ष, ईरान व अमेरिका चाहते हैं कि शांति स्थायी हो सके। पर इज़रायल द्वारा लेबनान की राजधानी बेरुत पर भारी बमबारी के बाद ईरान ने भी सऊदी अरब व अमेरिका के अन्य मित्र देशों पर बमबारी शुरु कर दी।**

पेझेशकियन करेंगे। हालांकि, ईरान पहले ही कह चुका था कि वह विटकॉफ़ या कुश्नर के साथ कोई बातचीत नहीं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शुक्रवार को नीतीश राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथ लेंगे

पर, वे कुछ समय बिहार के मु.मंत्री भी बने रहेंगे, अतः उनकी तुलना उड़ीसा के मु.मंत्री गिरधर गमांग से होना स्वाभाविक ही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। यह अकारण नहीं है कि नीतीश कुमार को बिहार का गिरिधर गमांग कहा जा रहा है। शुक्रवार को जब वे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे, तो वे गमांग की तरह ही उस दुर्लभ क्लब में शामिल होंगे, जहां कोई नेता एक ही समय में सांसद और मुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहा हो।

गमांग का दोहरा कार्यकाल एक और अधिक सनसनीखेज वजह के लिए जाना जाता है। वे 1998 में उस समय तक ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके थे, जब लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था। गमांग ने इस प्रस्ताव पर वोट डाला था, क्योंकि तब

- **गमांग, 1998 में उड़ीसा के मु.मंत्री बने थे, पर तभी प्र.मंत्री वाजपेयी की सरकार का लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था। गमांग उड़ीसा से विश्वास मत पर वोट देने दिल्ली आये थे, क्योंकि तब तक उन्होंने अपने सांसद के रुप में लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था, वाजपेयी जी की सरकार, एक मत से विश्वास प्राप्त करने से वंचित रह गई थी। ऐसी चर्चा थी कि इसमें गमांग के वोट की महत्वपूर्ण भूमिका थी।**
- **लगभग यह ही स्थिति नीतीश कुमार की है, वे राज्यसभा के सदस्य की शपथ तो लेने वाले हैं, पर अभी बिहार के मु.मंत्री पद पर भी स्थापित हैं।**

तक वे सांसद थे। वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई थी, जिसमें गमांग के वोट ने निर्णायक भूमिका निभाई थी।

कुमार से अपेक्षा नहीं है कि वे ऐसा करेंगे। शपथ लेने के बाद, उनके शीर्ष भाजपा नेताओं नरेन्द्र मोदी और अमित शाह सहित, अन्य नेताओं से मिलने की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'होर्मुज़ से एक दिन में सिर्फ 15 जहाज ही निकल सकेंगे'

तेहरान, 09 अप्रैल। अमेरिका-ईरान युद्ध विराम के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तासकी ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि अब ईरान एक दिन में होर्मुज से सिर्फ 15 जहाजों

- **रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास की ताज़ा रिपोर्ट में ईरान द्वारा कड़ी शर्तें लगाने की बात सामने आई है।**

को गुजरने की मंजूरी देगा। ईरान के इस फैसले से भारत में एलपीजी और कच्चे तेज की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सीमित आवाजाही के ईरान के इस फैसले ने अब वैश्विक ट्रांसपोर्टरों की चिंता भी बढ़ा दी है।

देश में एलीपी, क्रूड ऑयल और रसायन प्रोडेक्ट की सप्लाई को लेकर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या राघव चड्ढा नई पार्टी बनाने जा रहे हैं?

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपनी ही एक पोस्ट पर नई पार्टी बनाने के सुझाव पर ''दिलचस्प विचार'' की टिप्पणी कर अटकलों का बाज़ार गर्मा दिया

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राघव चड्ढा की एक रहस्यमयी टिप्पणी ने राजनीतिक अटकलों की लहर पैदा कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कभी पार्टी के प्रमुख चेहरे रहे चड्ढा संगठन में अपनी घटती हुई भूमिका के संकेतों के बीच नई राजनीतिक पहल करने पर विचार कर रहे हैं।

यह चर्चा तब शुरू हुई जब चड्ढा ने सोशल मीडिया पर आए एक सुझाव, कि उन्हें अपनी पार्टी बनानी चाहिए, का जवाब दिया और ''दिलचस्प विचार'' यह टिप्पणी भले ही सामान्य लग रही हो, लेकिन इसे राजनीतिक पुनर्संरचना के संकेत के रूप में देखा गया है, विशेषकर आप के भीतर हाल की घटनाओं को देखते हुए जो यह संकेत देती हैं कि राज्यसभा सांसद की भूमिका कम हो गई है।

- **राज्यसभा में आप पार्टी के उपनेता के पद से राघव चड्ढा को हटाने से यह साफ हो गया है कि पार्टी में राघव चड्ढा का कद कम हो गया है।**
- **यही नहीं हालिया महीनों में राघव ने भी पार्टी के कार्यों से दूरी बना ली थी, इससे आतंरिक मतभेदों की चर्चा भी तेज हो गई थी।**
- **विशेषज्ञों का कहना है कि नई पार्टी बनाने के सुझाव को ''दिलचस्प विचार'' करार देना एक सोचा समझा प्रयास है चर्चाओं में बने रहने का।**

चड्ढा को राज्यसभा में आप के उपनेता के पद से हटाए जाने ने यह धारणा मजबूत कर दी है कि पार्टी में उनका प्रभाव कम हुआ है। कभी पार्टी के सबसे मुखर और हाई प्रोफाइल नेताओं में से एक माने जाने वाले चड्ढा, ने हाल के महीनों में अपेक्षाकृत कम सार्वजनिक उपस्थिति दर्शाई, खासकर दिल्ली के बाहर पार्टी के विस्तार के मामले में। आंतरिक मतभेदों और पार्टी के भीतर भूमिकाओं के पुनर्गठन की खबरों ने उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों को और बढ़ा दिया है।

राघव चड्ढा के अपने संदेश ने भी जिज्ञासा बढ़ाई है। हाल ही में एक बयान में उन्होंने खुद के लिए कहा ''मौन हूं पर हारा नहीं हूं,'' जिसे राजनीतिक विश्लेषकों ने न केवल असंतोष का संकेत बल्कि प्रासंगिक बने रहने की इच्छा के रूप में पढ़ा है। जबकि उन्होंने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, शब्दों का चयन इस धारणा को और मजबूत करता है कि उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।

हालांकि, ऐसी कोई ठोस जानकारी नहीं है कि चड्ढा नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जो लोग स्थिति से परिचित हैं, उनका कहना है कि यह टिप्पणी ज्यादा निर्णायक घोषणा की बजाय मन की थाह लेने की कोशिश ज्यादा हो सकती है। यह एक तरह से विकल्प खुले रखने का तरीका है, किसी विशेष रास्ते के लिए प्रतिबद्ध हुए बिना। राजनीति की अस्थिर दुनिया में, ऐसी अस्पष्टता अक्सर रणनीतिक उपकरण के रूप में काम करती है, जिससे नेता विकल्प आज़मा सकते हैं, वो भी मौजूदा रास्तों को बंद किए बिना।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'छठी क्लास से तीसरी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य'

नई दिल्ली, 09 अप्रैल। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए, कक्षा 6 से तीसरी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। यह व्यवस्था शैक्षिणक सत्र 2026-27 से लागू होगी और स्कूलों को इसे सात दिनों के

- **सीबीएसई ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए यह घोषणा की और स्कूलों को 7 दिन में इसे लागू करने का निर्देश दिया।**

भीतर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, जिन स्कूलों ने अभी तक तीसरी भाषा की पढ़ाई शुरू नहीं की है, उन्हें तुरंत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पुस्तकों और संसाधनों की मदद से इसकी शुरुआत करनी होगी। साथ ही स्कूलों को यह भी तय कर जानकारी देनी होगी कि उन्होंने तीसरी भाषा के रूप में कौन-सी भाषा चुनी है।

'ट्रंप ने दबाव डाला था पाकिस्तान पर, ईरान के साथ अस्थायी सीज़फायर कराने का'

फायनैंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया तथा पाकिस्तान के स्वतंत्र कूटनीतिक रुख पर संदेह जताया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 9 अप्रैल। पाकिस्तान ने खुद को शांति स्थापित कराने वाला देश दिखाने की कोशिश भले ही की हो, ''फायनेंशियल टाइम्स'' की एक रिपोर्ट के अनुसार, वाइट हाउस ने ही इस्लामाबाद पर ईरान के साथ अस्थायी युद्धिवराम कराने के लिए दबाव डाला था।

यह रिपोर्ट पाकिस्तान की स्वतंत्र कूटनीतिक स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है और सुझाव देती है कि इस्लामाबाद कोई तटस्थ मध्यस्थ नहीं था, बल्कि अमेरिकी दबाव के लिए एक सुविधाजनक माध्यम था, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने इस्लामिक रिपब्लिक (ईरान) के खिलाफ धमकियां बढ़ाईं और दावा किया कि तेहरान शांति के लिए ''भीख मांग रहा था''।

रिपोर्ट में, घटनाओं से परिचित लोगों के हवाले से कहा गया है कि हफ्तों से ट्रम्प प्रशासन इस्लामाबाद पर दबाव डाल रहा था, ताकि ईरानियों को लड़ाई में विराम के लिए राजी किया जा सके, जिससे महत्वपूर्ण होर्मुज़ स्ट्रेट फिर से खुल सके।

रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान की अहम भूमिका, एक मुस्लिम बहुल पड़ोसी और मध्यस्थ के रूप में, इसे तेहरान तक पहुँचाने की थी।

इस्लामाबाद के बैक-चैनल प्रयास, जो पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख

- **रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन कई दिनों से पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि व ईरान को युद्ध विराम के लिए राज़ी करे ताकि होर्मुज़ स्ट्रेट खुल सके।**
- **इसका एक उद्देश्य यह भी था कि मुस्लिम पड़ोसी देश और मध्यस्थ के रुप में पाकिस्तान की भूमिका को तेहरान के समक्ष मजबूती से पेश किया जा सके।**
- **इसीलिए ट्रंप ने ईरान को पूर्ण रुप से नष्ट करने की धमकी दी फिर कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की और इसे ट्रंप ने तुरंत मान लिया, यह सब कुछ पूर्णतया प्रायोजित ''ड्रामा'' सा लगता है।**
- **विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप की चिंता तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर है, साथ ही अमेरिकी सेना के कमांडर भी अब युद्ध नहीं चाहते हैं।**

आसिम मुनीर के नेतृत्व किए गए थे, मंगलवार रात को अमेरिका, इज़राइल और ईरान के साथ दो सप्ताह के युद्धिवराम पर सहमति बनने के रूप में सामने आये।

यह घटनाक्रम ट्रंप की इस धमकी के बाद का है कि यदि तेहरान उसकी शर्तें पूरी नहीं करता तो वे ईरान की ''पूरी सभ्यता'' को नष्ट कर देंगे। लेकिन शांति वार्ता से परिचित लोगों के अनुसार, ट्रम्प तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित और ईरानी शासन की मजबूती देखकर हैरान थे।

रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी कमांडर इन चीफ ''युद्धिवराम के लिए उत्सुक'' थे, 21 मार्च को ईरान के पावर प्लांट्स को ''ध्वस्त'' करने की पहली धमकी के समय से ही।

''फायनेंशियल टाइम्स'' की रिपोर्ट के अनुसार, वॉशिंगटन और इस्लामाबाद का मानना था कि तेहरान द्वारा अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना उस स्थिति में ज्यादा थी, यदि इसे एक ऐसे मुस्लिम बहुल पड़ोसी राज्य द्वारा पहुँचाया जाए,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बारामती उपचुनाव से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी हटाया

मुंबई, 09 अप्रैल। महाराष्ट्र के बारामती विधान सभा उपचुनाव से कांग्रेस ने आज गुरुवार को अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन यह घोषणा की गई, जिससे अब इस चुनाव

- **बताया जाता है कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के फोन के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस बारे में घोषणा कर दी।**

के निर्विरोध होने की संभावना बन गई है। हालांकि अभी कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

खास बात यह रही कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के नेताओं के बार-बार अनुरोध के बावजूद निर्णय न लेने वाले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)